



उच्च शिक्षा की भूमिका: नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में

प्रतिभा यादव, शोधार्थी, आजीवन शिक्षा प्रसार एवं समाज कार्य अध्ययनशाला
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE



Author
प्रतिभा यादव

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 05/07/2023
Revised on : -----
Accepted on : 12/07/2023
Plagiarism : 03% on 05/07/2023



Plagiarism Checker X - Report
Originality Assessment

Overall Similarity: **3%**

Date: Jul 5, 2023

Statistics: 63 words Plagiarized / 2035 Total words

Remarks: Low similarity detected, check with your supervisor if changes are required.



शोध सार

21 वीं सदी के भारत के उत्थान के लिये नई शिक्षा नीति को लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों की सर्वांगीण विकास करना है। इस नीति में विद्यार्थियों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा, नवाचार और हस्त कौशल स्वभावलांबी होने पर बल दिया गया है। इस डॉफ्ट में शोध को बढ़ावा देने की संकल्पना स्पष्ट रूप से दिखी है। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वैश्विक दृष्टिकोण के साथ भारत केंद्रित है। उच्च शिक्षा में भी काफी रूप बदलाव की संकल्पना है। इस नीति विद्यार्थी को विषय की वाध्यता से छूट देने की बात कही गई है। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। इस नीति स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि 3 या 4 वर्ष के आधार पर उपाधि या प्रमाण पत्र या डिप्लोमा देने की व्यवस्था है। यदि विद्यार्थी स्नातक एक वर्ष का अध्ययन करता है। तो उस विद्यार्थी को डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा। इससे विद्यार्थी किसी स्नातक कोर्स मध्यावधि में अवरोध होने से उस कोर्स का ह्रास नहीं होगा।

मुख्य शब्द

पाठ्यक्रम, नई शिक्षा नीति, सर्वांगीण विकास, नवाचार, शिक्षा, ज्ञान.

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020), जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत प्रदान कर दी गयी। भारत की नई शिक्षा नीति शैक्षिक आधार को आत्मार्पित करती है। नई शिक्षा नीति ने 2020 ने शिक्षा नीति 1986 का स्थान ले लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्राथमिक और उच्च शिक्षा एव व्यवसायिक शिक्षा की एक व्यापक रूप रेखा तैयार की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली

को बदलना है। यह शिक्षा परम्परावादी एवं नवीन भौतिकवादी दोनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का मिश्रण है जिससे विद्यार्थियों में समन्वय वादी विचार धारा अर्न्तनिहित हो सके। इस नीति में जाति, लिंग, धर्म या पंथ और क्षेत्रवाद आदि भाव को समान रूप से स्थान दिया गया है और कोई भेदभाव भी नहीं किया गया है और समाज में सभी भेदभाव वाली मानसिकता को समाप्त करने का प्रयास किया गया है और उच्च शिक्षा गुणवत्ता युक्त हो और जन कल्याणकारी साबित हो जिससे समाज को एक सहयोगात्मक रूप में साबित हो। इस शिक्षा नीति के माध्यम भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने की दिशा में भी एक कदम है। इस नीति में यह परिकल्पना की गई है कि हमारे संस्थानों के समान पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र को छात्रों में मौलिक कर्तव्यों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करनी चाहिये और संवैधानिक मूल्यों, अपने देश और अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर अपने 'वसुदैव कुटुम्बकम्' का भाव जाग्रत हो। इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश के शिक्षार्थियों में ज्ञान, कौशल आत्मविश्वास, बुद्धि और कर्म के साथ न केवल विचार बल्कि मूल्यों और दृष्टिकोणों में भी विकास करना है जो मानव में, सतत विकास करना है। वैश्विक कल्याण के लिए एक जिम्मेदार प्रतिवद्धता, जिससे वास्तव में एक वैश्विक नागरिक प्रतिबिंबित होता है।

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य, ऐसे व्यक्तियों का विकास करना चाहिये उत्तम विचारशील और अच्छी रचनात्मक प्रवृत्ति हो। यह एक व्यक्ति में रूचि के साथ अभिरुचि के रूप में कार्य करे जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा, व्यक्तिगत, तकनीकी, व्यावसायिक विषयों सहित क्षेत्रों में गहराई से स्वाध्याय करने और चरित्र, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मक सेवा भाव और कौशल आधारित जीवन शैली के बढ़ावा की बात की गई है। नई शिक्षा नीति कुछ मौलिक परिवर्तन लाती है और इस नीति का मुख्य आकर्षक बहु-विषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं। नई शिक्षा नीति का मुख्य पाँच पिलर पर आधारित है जो कि है, वहनीयता, अभिगम्यता, गुणवत्ता, न्यायपरकता और जवाबदेही – और विद्यार्थियों में निरन्तर अधिगम प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए इस समाज और आज की आर्थिक माँग के अनुरूप भारतीय नागरिकों को तैयार करने की अनुशांसा की गई है जिससे नित नये कौशल हांसिल करना भी आवश्यक हो गया है। इस प्रकार हम कह सकते की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने की संकल्पना की गयी है और विद्यार्थियों में आजीवन अधिगम करते रहने की जिज्ञासा उत्पन्न करना है। नई शिक्षा नीति में पूर्ण रूप उत्पादक रोजगार और अच्छे अवसर उत्पन्न करने की बात करती है।

नई नीति 2020 अब पुरानी शिक्षा नीति 1986 का स्थान गृहण कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा ढाँचागत परिवर्तन प्रस्तावित है। इस में 5+3+3+4 के स्टेक्वर को अपनाने की बात की गई। अब शिक्षा में डिजिटल शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने की संकल्पना है जिससे 21 वीं सदी एक तकनीकी की सदी साबित होगी।

साहित्य की समीक्षा

इसके के अध्ययनों की समीक्षा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जो इस अध्ययन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्न्तनिहित है। इसमें नई शिक्षा नीति 2020 के विशेष रूप से उच्च शिक्षा से अध्ययनों पर किये कार्यों की स्पष्ट रूप से प्रभाव देखे जा सकते हैं।

पी.एस. ऐथल और शुभ्रज्योत्सना ऐथल के अनुसार उनके शोध पत्र "भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा 2020 का विश्लेषण इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में।" भारतीय शिक्षा नीति 2020 की गुणवत्ता, आकर्षण संदर्भ सामर्थ में सुधार के लिये नवीन नीतियाँ बनाकर और निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षा को खोलकर आपूर्ति बढ़ाने के लिये और साथ ही बनाये रखने के लिए सख्त नियंत्रण के साथ इस तरह उद्देश्य को प्रतिपादित किया है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोधपत्र में मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण बिन्दु पर प्रकाश डाला गया है परन्तु नई शिक्षा नीति 2020 से संबन्धित प्राथमिक और गौण दत्त का विश्लेषण करना है। इसके अन्य मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- नई शिक्षा नीति 2020 को पेश करना।

- नई शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव उच्च शिक्षा में प्रभावकारी बदलाव देखना।
- उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण गुणवत्ता के कारण सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि को दर्शाने के लिये।
- शैक्षिक खर्च के लिये नई शिक्षा नीति 2020 में सकल उत्पाद में 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत की अनुशंसा की गयी है।

अनुसंधान की क्रिया विधि

इस अध्ययन में पाठ्यक्रम आलोचनात्मक मूल्यांकन, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और व्याख्यानात्मक प्रविधि का उपयोग करते हुये प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े के माध्यम से उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ के साथ एक महत्वपूर्ण दृष्टि के रूप में नई शिक्षा नीति 2020 के संपूर्ण अध्ययन पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

दत्त संकलन

शोध अध्ययन के लिये प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों से दत्तों का संकलन किया गया है जिसके आधार पर सम्पूर्ण आलेख का विश्लेषण किया गया है।

प्राथमिक स्रोत

प्राथमिक संसाधन के रूप में नई शिक्षा नीति 2020 का मूल अभिलेख का अध्ययन कर दत्त प्राप्त किया गया है जो केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित है।

द्वितीयक स्रोत

द्वितीयक स्रोत के लिये शोधार्थी ने नई शिक्षा नीति 2020 से सम्बन्धित पुस्तकें और शोध पत्र, शोध रिपोर्ट, शोध प्रबन्ध, न्यूज पेपर, पत्रिका 'विकिपीडिया, ब्रिटानिका, आदि अन्य संसाधन इत्यादि।

अध्ययन का उपयोगार्थ

मूल तथ्यों पर आधारित इस अध्ययन का विमर्श से यह महसूस किया की समाज में एक नई शिक्षा नीति का कार्य करेगी। इस अध्ययन से पूर्व के क्षेत्र में अनुसंधान की कमी के कारण यह शोध मॉडल इस अध्ययन के लिये प्रस्तावित है। शोधकर्ता इस वर्तमान अध्ययन के सभी पहलुओं को समझाने का प्रयास करेगा। वर्तमान शोध नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में पाठकों के बीच जागरूकता पैदा करने का प्रयास करेगा और संदर्भ पाठ्य सामग्री भी तैयार करना और अग्रिम भविष्य में अपार सम्भावना की आशा की जायेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

उच्च शिक्षा गुणात्मक परिभार्जन यह शिक्षा नीति कुछ हद तक डॉ. राधाकृष्णन के विचार से मेल खाती दिख रही है। इस ड्राफ्ट में ग्रामीण एवं नगरी शिक्षा व प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण में परिवर्तन काल के लिये एक व्यापक ढांचा है। इस नीति का उद्देश्य 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को परिमार्जित रूप देना है। नई शिक्षा को विद्यालय शिक्षा से विश्वविद्यालय स्तर तक प्रणाली में औपचारिक परिवर्तन को औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से पेश किया गया। समाज के बदलते दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये, अब से शैक्षिक सामग्री प्रमुख अवधारणाओं, विचारों अनुप्रयोगों और समस्या समाधान के दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित करेगी। नई शिक्षा नीति के माध्यम से देश में उच्च शिक्षा में अमूल-चूक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इस नीति में सकारात्मकता एवं दीर्घकालीन उन्मुखी भविष्य की संकल्पना निहित है।

अतः नई शिक्षा नीति 2020 आशाओं से भरी हैं। यह तक विदेशी विश्वविद्यालय को शैक्षिक परिसर स्थापित करने की बात कही गई जो कि यह एक सराहनीय पहल है। इससे विद्यार्थियों को अपने देश की समुन्नत शिक्षा का अध्ययन करने का अनुभव होगा। बहु विषयक प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थियों में मानविकी विषय के क्षेत्र में रुचि जाग्रत होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा में सम्भाव्य

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (जी ई आर) को मौजूदा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए NEP 2020 की कल्पना की गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है। इसका उद्देश्य मुक्त और दूरस्त शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा और शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिये मूलभूत ढांचे को और विकसित करना है जिससे विद्यार्थियों का समग्र व्यक्तित्व का विकास संभव हो।

इससे अलावा, देश में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना की जायेगी जो कि सम्पूर्ण भारत उच्च शिक्षा के लिये एक ही विनियामक के रूप में परिकल्पित एक राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (NAAC) की स्थापना की जायेगी। भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (HECT) में विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने के लिये कई कार्य क्षेत्र होंगे। शैक्षिक क्षेत्र में सभी भर्तीओं के लिये एक बोर्ड का गठन किया जायेगा। अखण्ड भारत के लिये पात्रता को समान लागू करने की बात की गई है।

साइबर सुरक्षा में शिक्षा एवं कौशल

विश्व आर्थिक मंच 2021 की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 के अनुसार साइबर सुरक्षा विफलता विश्व के लिये चौथा अति महत्वपूर्ण खतरा है। जैसा कि चल रही महामारी के कारण शिक्षा और अध्ययन पहले ही साइबर स्पेस में चली गई है। प्रत्येक व्यक्ति को गोपनीय सुरक्षा करना अति महत्वपूर्ण हो गया है। परन्तु भारत सरकार डिजिटलीकरण को काफी प्रोत्साहन दे रही है। इस लिये ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। हमारे नेटवर्क और साइबर स्पेस को सुनिश्चित बनाना अत्यन्त आवश्यक है। आधुनिक परिदृश्य में यह एक प्रासंगिक हो जाता है। 'साइबर सुरक्षा लचीलापन' के लिये क्षमता निर्माण को प्रमुख महत्व दिया जाता है।

उच्च शिक्षा में नवाचार युक्त शिक्षा प्रणाली

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रमुख क्षेत्रों में सरकारी एवं निजी और उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान एवं विकास निवेश को प्रोत्साहित करना है। इससे इनोवेशन और इनोवेटिव माइंडसेट को बढ़ावा मिलेगा। इसे सुगम बनाने के लिये व्यवसाय आधारित कौशल का विकास करना हम सब का केन्द्र बिन्दु है।

अतः "बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)" के बारे में ज्ञान बढ़ाने और इससे लाभ प्रदान करने के लिए इसके संरक्षण के लिये कौशल को विकसित करना अस्वाभाविक हो जाता है।

निष्कर्ष

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नूतन परिवर्तन ले कर आयी है। यह विद्यार्थियों को खुला चिंतन करने और अपनी रुचि के आधार पर अध्ययन करने पर विशेष बल दिया गया है। यह विद्यार्थियों के लिये ओपेन माइंड लर्निंग की बात कही गयी है जिससे उनके अन्तर्निहित को प्रकाशमय किया जा सके। यह नीति विद्यार्थियों में रुचि परक कौशल में प्रशिक्षण की बात करती है। यह नीति शिक्षार्थियों को रोजगार क्षमता में वृद्धि को ध्यान में रखती है। नयी शिक्षा नीति की सफलता इसके सफल क्रियान्वयन पर निर्भर करती हैं।

संदर्भ सूची

1. (2020), *राष्ट्रीय शिक्षा नीति*, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 4-8।
2. धोत्रे संजय, (2020), *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, योजना पत्रिका*, सूचना भवन प्रकाशन, नई दिल्ली, अंक सितंबर।
3. रावत, अरविन्दु, (2022) *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: समतामूलक और समावेशी शिक्षा क्रियान्वयन में अध्यापक शिक्षा की चुनौतियाँ, अमोघवार्ता*, अदिति प्रकाशन, रायपुर छत्तीसगढ़, ISSN 2583-3189 (Online), 2583-0775 (Print) दिसंबर-फरवरी, पृ. 60-62।
4. (2021), *नयी शिक्षा नीति में प्रौद्योगिकी पर जोर, नईदुनिया समाचार पत्र*, इंदौर प्रकाशन, दिसंबर 26, पृ.

5।

5. चंद्राकर, क्षमा, (2022) भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, *शोध समागम*, (ऑनलाइन), अदिति प्रकाशन, रायपुर छत्तीसगढ़, वर्ष 03, अंक 02, अप्रैल-जून, पृ.579-582।
6. कुमार, राजीव, (2022) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उच्च शिक्षा, *शोध समागम* (ऑनलाइन) अदिति प्रकाशन रायपुर छत्तीसगढ़, ISSN 2581-6918 Vol. 05, ISSUE-03 जुलाई से सितम्बर 2002 पृ. 860-865।
7. सिंह विरेंद्र, देवी कुकन (2022) उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 की एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि, *IJRAR-ORG* (Online) E-ISSN 2348-1269 जनवरी 2022 Vol.-9- Issue-1 पृष्ठ 1720।

